SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN POLITY BY-

SUJEET BAJPAI SIR

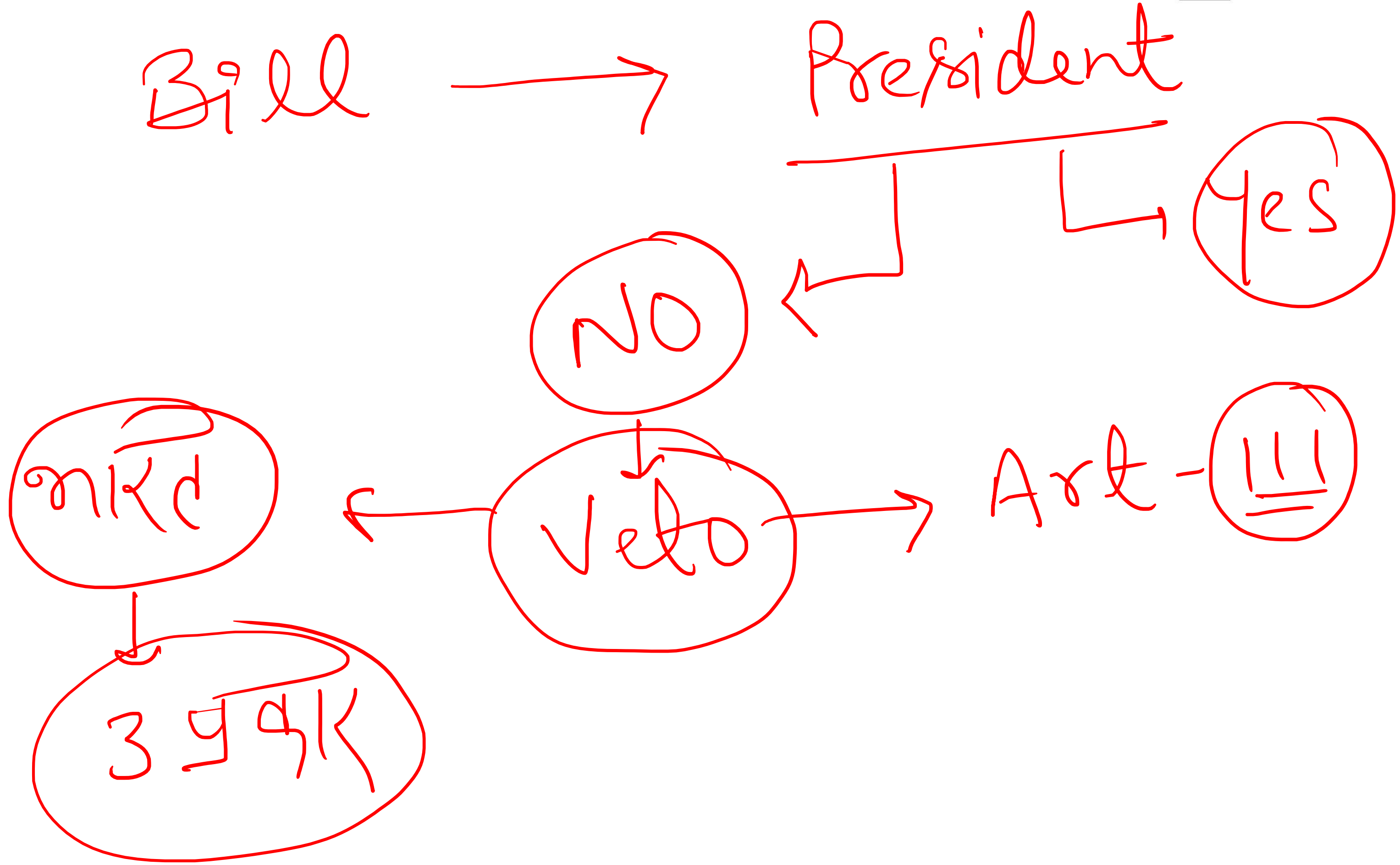
Bill
President
Yes
NO
Veto
Art - 111
भारत
3 प्रकार

Veto Power of the President

A bill passed by the Parliament can become an act only if it receives the assent of the President.

When such a bill is presented to the President for his assent, he has three alternatives (under Article 111 of the Constitution):

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

राष्ट्रपति की वीटो पावर संसद द्वारा पारित विधेयक तभी एक अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। जब इस तरह के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प (संविधान के अनुच्छेद १११ के तहत):

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

1. Absolute veto, that is, withholding of assent to the bill passed by the legislature.

2 3. Suspensive veto, which can be over ridden by the legislature with an ordinary majority.

3 4. Pocket veto, that is, taking no action on the bill passed by the legislature.

1. पूर्ण वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोक देना ।

3. सुस्पेंसिव वीटो, जो एक साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा ग्रस्त हो सकता है ।

4. पॉकेट वीटो, यानी विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Ordinance-making Power of the President

Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament.

These ordinances have the same force and effect as an act of Parliament, but are in the nature of temporary laws.

Max Time ⇒ 6 माह + 6 weeks

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।

इन अध्यादेशों में संसद के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है, लेकिन यह अस्थायी कानूनों की प्रकृति में होता है ।

क्षमादान की शक्ति
↓
Art 72

Pardoning Power of the President(Article-72)

सबसे बड़ा क्षमादान (Amnesty)

1.Pardon It removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.

2.Commutation It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form.

For example, a death sentence may be commuted to rigorous imprisonment, which in turn may be commuted to a simple imprisonment.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति (अनुच्छेद-72)

1. क्षमा यह सजा और सजा दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी वाक्यों, दंड और अयोग्यता से पूरी तरह से मुक्त करता है।

2. कम्यूटेशन यह एक हल्के रूप के लिए सजा के एक रूप के प्रतिस्थापन को दर्शाता है।

उदाहरण के लिए, मौत की सजा को कठोर कारावास में बदल दिया जा सकता है, जिसे बदले में साधारण कारावास में बदल दिया जा सकता है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

3.Remission It implies reducing the period of sentence without changing its character.

For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years may be remitted to rigorous imprisonment for one year.

3. छूट यह अपने चरित्र को बदलने के बिना वाक्य की अवधि को कम करने का तात्पर्य है।

उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास तक भेजा जा सकता है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

4.

Respite It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender.

4. राहत यह मूल रूप से कुछ विशेष तथ्य के कारण दिए गए एक के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है, जैसे किसी दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

5. Reprieve It implies a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period.

Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the President.

5. राहत यह एक अस्थाई अवधि के लिए एक वाक्य (विशेष रूप से मौत की है कि) के निष्पादन के रहने का तात्पर्य है ।

इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समय देना है ।

Under Article 161 of the Constitution, the governor of a state also possesses the pardoning power.

Hence, the governor can also grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against a state law.

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा शक्ति भी है।

इसलिए, राज्यपाल राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट या निलंबित, परिहार और लघुकरण भी प्रदान कर सकते हैं ।

But, the pardoning power of the governor differs from that of the President in following two respects:

1.The President can pardon sentences inflicted by court martial (military courts) while the governor cannot.

लेकिन, राज्यपाल की क्षमा शक्ति दो मामलों का पालन करने में राष्ट्रपति से अलग है:

1. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालतों) द्वारा दिए गए वाक्यों को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते ।

2. The President can pardon death sentence while governor cannot.

Even if a state law prescribes death sentence, the power to grant pardon lies with the President and not the governor.

2. राष्ट्रपति मौत की सजा क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते ।

यहां तक कि अगर एक राज्य के कानून मौत की सजा निर्धारित करता है, क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति और नहीं राज्यपाल के पास है ।

⇒ Prime minister

In the scheme of parliamentary system of government provided by the constitution, the President is the nominal executive authority (de jure executive) and Prime Minister is the real executive authority (de facto executive).

संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में, राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकरण (डी ज्यूर कार्यकारी) है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण (वास्तविक कार्यकारी) है ।

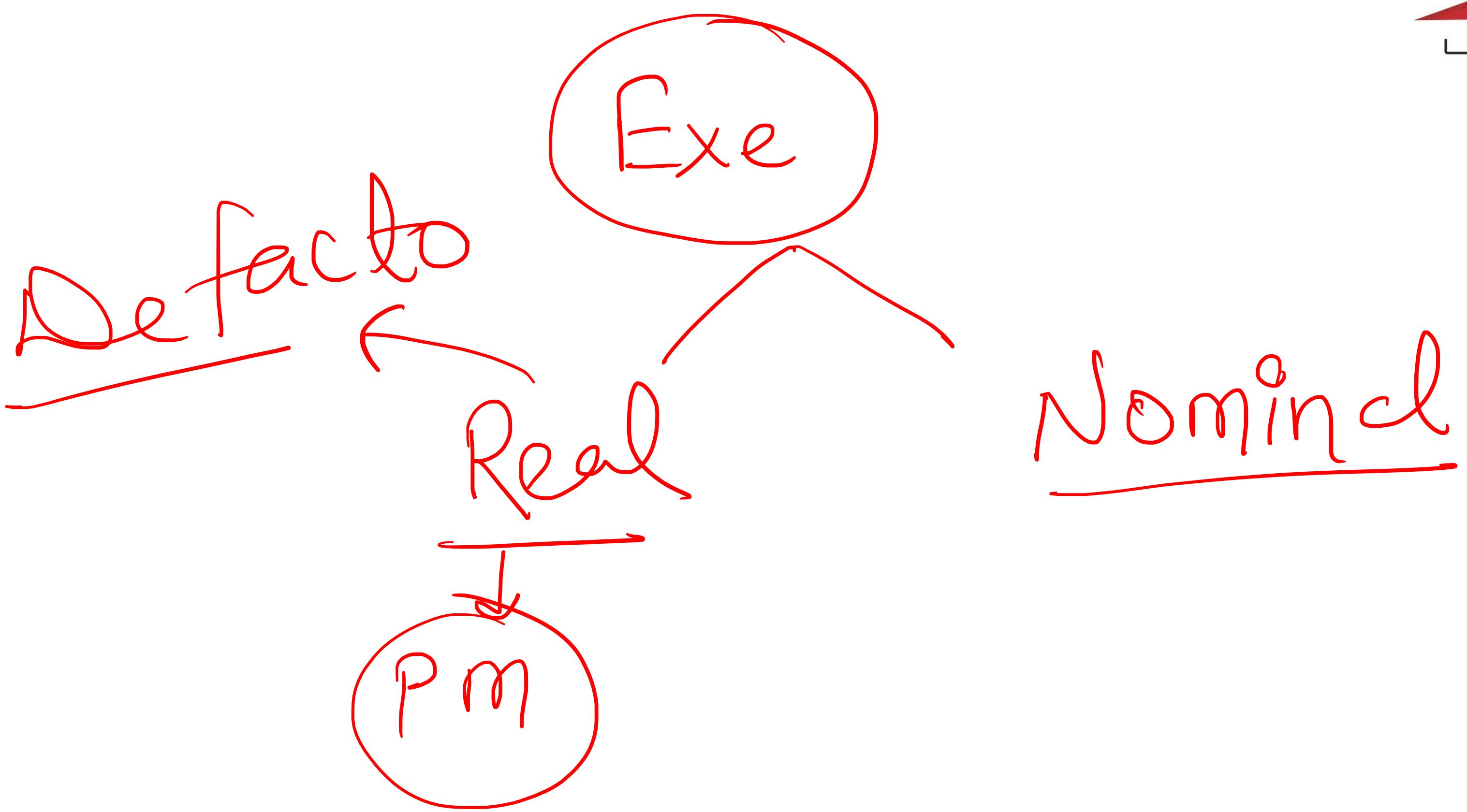
Exe
Defacto
Real
Nominal
PM

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

PM

elected ✗

Appointed ✓

नियुक्त

Appointment of the Prime Minister

The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Article 75 says only that the Prime Minister shall be appointed by the president.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

In accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister.

सरकार की संसदीय प्रणाली के अधिवेशनों के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है।

But, when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the President may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the Prime Minister.

लेकिन, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है।

In such a situation, the President usually appoints the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as the Prime Minister and asks him to seek a vote of confidence in the House within a month.

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उन्हें एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत मांगने को कहते हैं।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

This discretion was exercised by the President, for the first time in 1979, when Neelam Sanjiva Reddy (the then President) appointed Charan Singh (the coalition leader) as the Prime Minister after the fall of the Janata Party government headed by Morarji Desai.

राष्ट्रपति ने इस विवेक का प्रयोग पहली बार 1979 में किया था, जब नीलम संजीव रेड्डी (तत्कालीन राष्ट्रपति) ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह (गठबंधन के नेता) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था ।

However, if, on the death of an incumbent Prime Minister, the ruling party elects a new leader, the President has no choice but to appoint him as Prime Minister.

हालांकि, अगर किसी मौजूदा प्रधानमंत्री की मौत पर सत्तारूढ़ दल नए नेता का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति के पास उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

In 1997, the Supreme Court held that a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for six months, within which, he should become a member of either House of Parliament; otherwise, he ceases to be the Prime Minister.

१९९७ में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, वह प्रधानमंत्री बने रहते हैं ।

The term of the Prime Minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the president.

However, this does not mean that the president can dismiss the Prime Minister at any time.

So long as the Prime Minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President.

However, if he loses the confidence of the Lok Sabha, he must resign or the President can dismiss him.

प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं।

जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता ।

हालांकि अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं।

Collective Responsibility

The fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility.

Article 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

सामूहिक जिम्मेदारी

सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्यशील मौलिक सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ।

अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of ommission and commission.

They work as a team and swim or sink together.

इसका मतलब यह है कि सभी मंत्रियों के पास अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी है ।

वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

15% of LS
member

मंत्रि परिषद्
↓
Council of Minister

80-90 मंत्री

संविधान (Art-75)

V/S

मंत्रि मंडल
↓
Cabinet

6-7 मंत्री

संविधान (रत)
(वर्णन ✗)

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

मंत्रिमंडल
(वर्तमान मे)
संविधान मे
1 बार
(Art 352)

Appointment of Governor

The governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college as is the case with the president.

He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. In a way, he is a nominee of the Central government.

राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल न तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप् से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है ।

उसके हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

एक तरह से वह केंद्र सरकार के उम्मीदवार हैं।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Term of Governor's Office

A governor holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

However, this term of five years is subject to the pleasure of the President.

Further, he can resign at any time by addressing a resignation letter to the President.

राज्यपाल कार्यालय का कार्यकाल एक राज्यपाल उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए कार्यालय रखता है जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है ।

हालांकि, पांच साल का यह कार्यकाल राष्ट्रपति की खुशी के अधीन है ।

अलावा राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र देकर वह ◌ारा कतई भी इस्तीफा दे सकते हैं।

The powers and functions of the governor can be studied under the following heads:

1. **Executive powers.**
2. **Legislative powers.**
3. **Financial powers.**
4. **Judicial powers.**

1. Executive powers.

1.

He appoints the chief minister and other ministers. They also hold office during his pleasure.

1. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
वे अपनी प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करते हैं ।

2.

He appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. The advocate general holds office during the pleasure of the governor.

2. वह किसी राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है।

एडवोकेट जनरल राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।

Highest Law officer
state

Art 165

3.

He appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court.

3. वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और उनकी सेवा शर्तों और पद के कार्यकाल का निर्धारण करते हैं ।

हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल समान तरीके से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान आधार पर हटाया जा सकता है ।

4.

He appoints the chairman and members of the state public service commission.

However, they can be removed only by the president and not by a governor.

4. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है न कि किसी राज्यपाल द्वारा ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

2. Legislative powers.

A governor is an integral part of the state legislature. In that capacity, he has the following legislative powers and functions:

1. He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly.

एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उस क्षमता में, उसके पास निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य हैं:

1. वह राज्य विधानमंडल को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है ।

2. He can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.

2. वह प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं ।

3. He nominates one-sixth of the members of the state legislative council from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service.

3. वह साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच से राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है ।

4. He can nominate one member to the state legislature assembly from the Anglo-Indian Community.

5.He can promulgate ordinances when the state legislature is not in session.

These ordinances must be approved by the state legislature legislature within six weeks from its reassembly.

5. जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं होता है तो वह अध्यादेश ◌ो◌ं को प्रख्यापित कर सकता है ।

इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी पुनर्विधानसभा से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

SC/HC

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

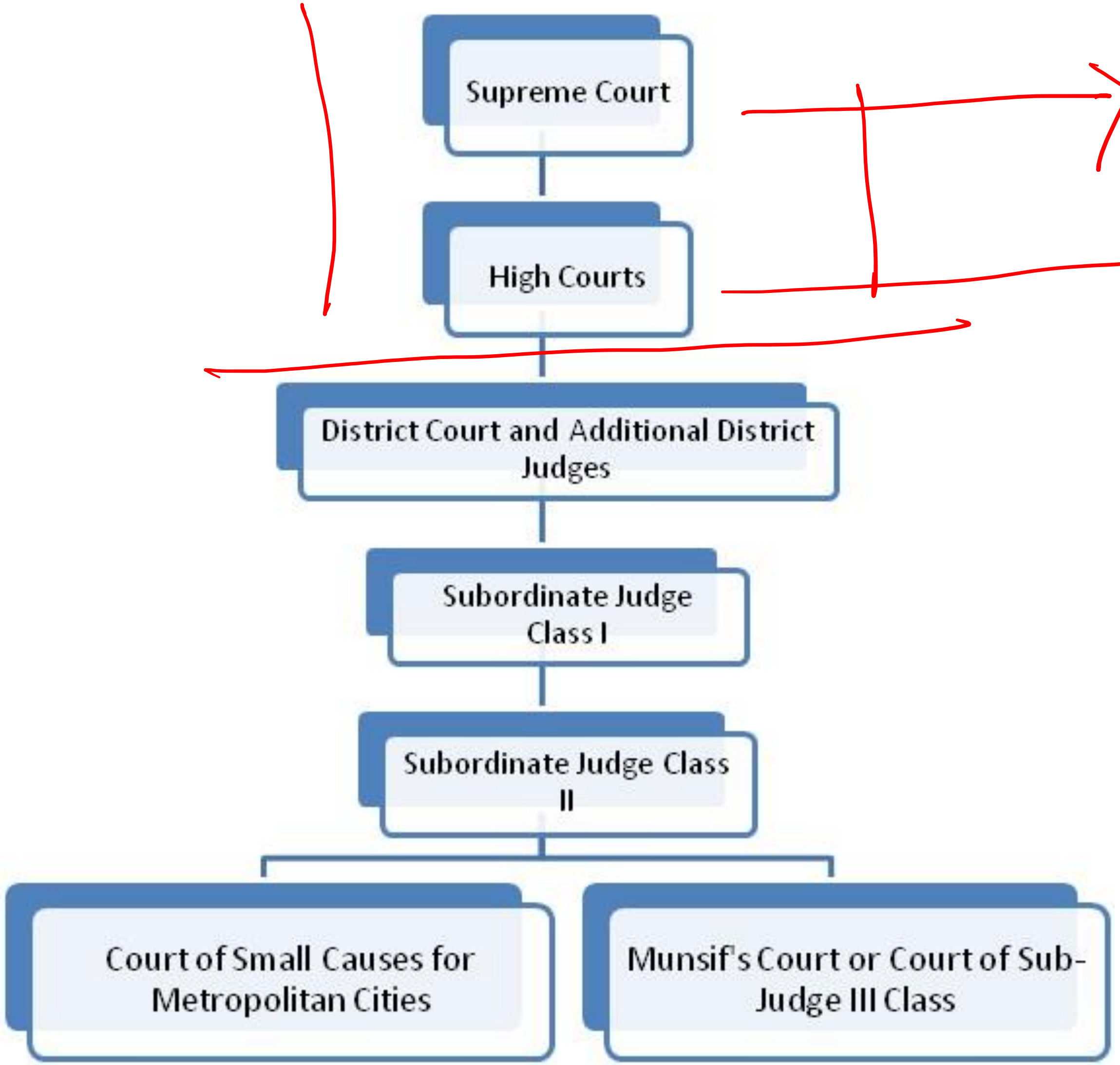

Supreme Court

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950.

It succeeded the Federal Court of India, established under the Government of India Act of 1935.

However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor.

This is because, the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था।

यह भारत के संघीय न्यायालय, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित सफल रहा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में बदल दिया है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

124.	Establishment and Constitution of Supreme Court
124A.	National Judicial Appointments Commission
124B.	Functions of Commission
124C.	Power of Parliament to make law
125.	Salaries, etc., of Judges
126.	Appointment of acting Chief Justice
127.	Appointment of *ad hoc* Judges
128.	Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court

- There are currently 32 judges (including the Chief Justice of India) and maximum possible strength is **34.**

- Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at eight (one chief justice and seven other judges).

Appointment of Judges

The judges of the Supreme Court are appointed by the president.

The chief justice is appointed by the president after consultation with such judges of the Supreme Court and high courts as he deems necessary. (कोलेजियम की सिफारिश)

न्यायाधीशों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

The other judges are appointed by president after consultation with the chief justice and such other judges of the Supreme Court and the high courts as he deems necessary.

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

Tenure of Judges

The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court.

He holds office until he attains the age of 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by Parliament.

न्यायाधीशों का कार्यकाल

संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का कार्यकाल तय नहीं किया है।

वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ले।

उनकी आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान किए गए इस प्रकार से निर्धारित किया जाना है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Removal of Judges